(d) The allocations of imported palmolein to States/UTs from the Central Pool during February-October, 1996 have been suitably restricted so as to keep within the permitted limit of total import of 2.00 lakh MTs. Accordingly the allocations to the major palmolein consuming States like Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have been reduced vis-a-vis the demand received from them. Central Government is making available the allocated quantity of imported palmolein from the storage point of STC/HVOC to the nominees of the respective States/ UTs. The responsibility for further movement/distribution of the edible oil rests with the State Government/UT Administrations.

Export of Marine Products from Andhra Pradesh

870. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that exports of marine products have declined from Andhra Pradesh in 1995-96;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether MPEDA has not given sufficient emphasis to marine exports from Andhra Pradesh; and

(d) if so, the reasons and details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) The exports of marine products from Andhra Pradesh have declined in terms of value in year 1995-96. The decline is attributed to recurrence of disease in some of the shrimp farming areas, forcing the farmers to harvest under sized shrimp. Besides this the sluggish economic condition prevailing in Japan, a major market for shrimps, was also a factor contributing to the decline.

(c) No Sir

(d) Does not arise.

Comprehensive Central Legislation for Agricultural Workers

871. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether draft comprehensive central legislation for agricultural workers has been prepared;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) by when it is likely to be introduced in Parliament?

THE MINISTER OF LABOUR (SHIR M. ARUNACHALAM): (a) Yes,
Sir.

(b) The proposal seeks to provide for regulation of employment and conditions of service of agricultural workers and to provide for their welfare.

(c) The proposal is at an advanced stage of consideration and the necessary Bill will be introduced in the Parliament as soon as possible.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण हेतु चीनी की प्राप्ति

872. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू अवधि में लेवी प्रणाली के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु प्राप्त की गयी चीनी की मात्रा कितनी है;

(ख) घरेलू उत्पादन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) आशापूर्ण घरेलू उत्पादन आंकड़ों के बावजूद राज्य व्यापार निगम (एम०टी०सी०) और खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) द्वारा चीनी का आयात किये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) 1995-96 में लगभग 68 लाख टन लेवी

चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध है। इसके विपरीत लगभग 48 लाख टन की वर्तमान आवश्यकता है।

(ग) चीनी की वर्ष 1 अक्तूबर, 1995 से 30 सितम्बर, 1996 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी के आयात का कोई भी अनुबंध एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० द्वारा नहीं किया गया है।

छोटे और कुटीर उद्योग

873. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में स्थित छोटे और कुटीर उद्योगों को केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये के कारण समुचित रूप से विकसित नहीं किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में छोटे और कुटीर उद्योगों का कुल उत्पादन कितना था और इस अवधि के दौरान इन उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) देश में छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और पिछले तीन वर्षों में इन उद्योगों के विकास के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु क्षेत्र और खादी और ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन और रोजगार के अनुमान इस प्रकार है:—

	लघु उद्योग		खादी और ग्रामीण उद्योग	
वर्ष	उत्पादन (वर्तमान मूल्यों पर) (करोड़ रु० में)	रोजगार (लाख संख्या में)	उत्पादन (करोड़ रु० में)	रोजगार (लाख संख्या में)
1993-94	241648	139.38	3233.86	53.28
1994-95	293990	146.56	3624.06	53.46
1995-96 (अ)	316421	152.61	4470.00	60.50

(अ) अनुमानित

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:—

(1) उद्यमिता विकास (2) निरीक्षण, मार्गदर्शन, कार्यशाला, परीक्षण, टूल रूम और उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास संबंधी सुविधाओं के द्वारा तकनीकी सहायता (3) मूल्य और क्रय वरीयता के जरिये और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा विपणन सहायता (4) विकसित औद्योगिक भूखण्डों, शैडों इत्यादि के जरिये राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचनात्मक सहायता (5) वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय और पूंजी संबंधी सहायता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र योजना संबंधी परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है:—

(करोड़ रुपये)

	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 बजट अनुमान
लघु उद्योग (सीडो + एम०एस०-आई०सी०)	155.95	205.81	250.60
खादी और ग्रामोद्योग आयोग	195.50	205.00	343.00

Privatisation of Coal Mines

874. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to privatise coal mines;

(b) if so, the action taken so far in this direction; and

(c) the details thereof?